भारत - रवांडा संबंध

भारत रवांडा संबंध सौहार्द विचारों के अभिसरण तथा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग, द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ता हुआ रूझान और निवेश, बड़े लोगों का आपस में संपर्क तथा आपसी सम्मान की गहन समझ पर आधारित है।

भारत विश्व के ऐसे कुछ देशों में से है जिन्होंने विश्व को पूर्व में 1992 से ही नरसंहार की संभावना के बारे में अपनी चिंता जतानी शुरू कर दी थी। 1994 के नरसंहार के दौरान, भारतीय सैनिक, यू एन ए एम आई आर के एक भाग के रूप में ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों की आहूति दी थी।

1999 में रवांडा ने दिल्ली में एक उच्चायोग की स्थापना की थी। प्रथम रवांडा उपायुक्त की भारत में नियुक्ति 2001 में हुई थी। भारतीय उच्चायोग काम्पाला, युगांडा को उच्चायोग रवांडा की अतिरिक्त समवर्ती जिम्मेवारी सौंपी गई है। रवांडा ने भारत अर्थात मुम्बई और बैंगलौर में दो मानद राजदूत नियुक्त किए हैं।

उच्च स्तरीय दौरों का आदान - प्रदान

राष्ट्रपति पॉल कगामे ने निजी तौर पर भारत का तीन बार दौरा किया था। दिसम्बर, 2002 में उन्होंने वेल्लौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी से डाक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने के लिए भारत का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति कगामे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे। राष्ट्रपति कगामे ने जनवरी, 2009 में फिक्की द्वारा आयोजित भारत - अफ्रीका व्यवसाय मंच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए फिर से नई दिल्ली का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मिले थे। अभी हाल ही में, राष्ट्रपति कगामे ने भारतीय आर्थिक मंच में शामिल होने के लिए नवंबर, 2014 में नई दिल्ली का दौरा किया था। अपने दौरे के दौरान वे माननीय राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी से मिले थे।

रवांडा के प्रधानमंत्री बर्नाड माकुजा ने जनवरी, 2011 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर बैठक में भाग लिया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मुलाकात की। रवांडा के प्रधानमंत्री गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे।

श्री चार्ल्स मुरीगंडे, रंवाडा के विदेश मंत्री ने मार्च, 2003 में भारत का दौरा किया था। दौरे के दौरान भारत तथा रवांडा के मध्य द्विपक्षीय सहयोग पर आम करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

वर्ष 2006 में भारत से रवांडा का प्रथम मंत्रिमंडलीय दौरा किया गया। लघु स्तर उद्योग, कृषि तथा ग्रामीण उद्योग के माननीय मंत्री श्री महाबीर प्रसाद ने अगस्त, 2006 में रवांडा का दौरा किया था। दौरे के दौरान लघु स्तर उद्योग में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

कृषि राज्य मंत्री श्री कांति लाल भूरिया ने मई, 2007 में रवांडा का दौरा किया था तथा कृषि और पशु संसाधनों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

श्री अरूण यादव, कृषि तथा खाद्य संसाधन उद्योग राज्य मंत्री ने मई, 2011 में सेक्टोरल समर्थन को उन्नत तथा मजबूत बनाने के लिए रवांडा का दौरा किया था।

रवांडा के पूर्व प्रधानमंत्री तथा सीनेटर वर्नाड मकूजा की अगुवाई में एक 25 सदस्यीय व्यवसाय प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के नए अवसरों की तलाश में अक्टूबर, 2011 में भारत का दौरा किया। रवांडा विकास बोर्ड द्वारा भारतीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम संघ, नई दिल्ली के सहयोग से एक रोड - शो का आयोजन किया गया था जिसमें व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यम, प्रौद्योगिकी आपूर्ति एवं व्यापक स्पेक्ट्रम भर में विशेषज्ञों की आउटसोर्सिंग दोनों पक्षों ने कृषि संसाधन एवं पैकेजिंग, निर्माण, औषधीय, कपड़ा बैंकिग तथा वित्तीय सेवाओं में व्यवसाय के अवसरों को तलाशा गया। खनन तथा ऊर्जा में सहयोग जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है पर भी विचार - विमर्श किया गया था।

विदेश राज्य मंत्री श्रीमती प्रनीत कौर की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 15 - 16 फरवरी, 2012 को रवांडा का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय से मंत्रिमंडलीय स्तर पर रवांडा का यह प्रथम दौरा था। विभिन्न सेक्टरों से 22 व्यावसायिक अधिकारियों को शामिल करते हुए एक सी आई आई व्यवसाय प्रतिनिधिमंडल ने भी सरकारी प्रतिनिधि मंडाल का साथ दिया। दौरे के दौरान एक द्विपक्षीय संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए एक करार एवं ग्रामीण रवांडा में 35 सकूलों में नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग और सौर ऊर्जा पर दो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 35 स्कूलों की ओर विद्युतीकरण को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के तहत पूरा किया गया।

अप्रैल, 2012 में, जनरल जेम्स काबेरेबे, रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 'डेफ एक्स्पो इंडिया 2012' में उपस्थित होने के लिए भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान वे भारत के माननीय रक्षा मंत्री से मिले तथा उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य भविष्य में संभाव्य सहयोग पर विचार विमर्श किया।

रवांडा की संसद की माननीय स्पीकर श्रीमती रोज मुकांताबाना ने नई दिल्ली में अक्टूबर, 2012 में आयोजित संसद की महिला स्पीकरों की बैठक में भाग लिया।

डॉ0 एग्नेस माटिल्डा कालीबाटा, कृषि तथा पशु संसाधन मंत्री ने माननीय जल संसाधन मंत्री श्री हरीश रावत के आमंत्रण पर जनवरी, 2013 में भारत का दौरा किया। दौरे के दौरान दोनों पक्षों के मध्य सिंचाई तथा क्षमता निर्माण पर बल देते हुए जल संसाधन प्रबंधन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे।

नवम्बर, 2013 सुक्ष्म, लघु तथा मध्य उद्यम के लिए माननीय राज्य मंत्री श्री के एच मुनीयप्पा की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण एक्सपो तथा विचार गोष्ठी में भाग लेने के लिए किगाली का दौरा किया।

फरवरी, 2014 में रवांडा के अवसंरचना मंत्री प्रोफेसर सिलास लवा कावा मावा ने अफ्रीका से संबंधित यू एन आर्थिक सहयोग (यू एन ई सी ए) के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। वे तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिंया से भी मिले थे।

जनवरी, 2015 में सुक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम के केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने भारत सरकार के सहयोग के अंतर्गत स्थापित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन के लिए किगाली का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वे राष्ट्रपति कगामे से भी मिले थे। उन्होंने रवांडा के शिक्षा, व्यापार एवं टी वी ई टी के मंत्रीयों के साथ भी बैठक की थी।

जनवरी, 2015 में सुक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम के केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने भारत सरकार के सहयोग के अंतर्गत स्थापित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के उद्घाटन के लिए किगाली का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वे राष्ट्रपति कगामे से भी मिले थे। उन्होंने रवांडा के शिक्षा, व्यापार एवं टी वी ई टी के मंत्रीयों के साथ भी बैठक की थी।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री सुदर्शन भगत ने आई ए एफ एस-III के लिए राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को निमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में जुलाई 2015 में रवांडा का दौरा किया।

क्षमतावर्धन तथा विकास भागीदारी :-

रवांडा के साथ भारत की भागीदारी तीन स्तरों पर है, अर्थात अफ्रीकी संघ (ए यू) स्तर पर, क्षेत्रीय आर्थिक समतियों (आर ई सी) के स्तर पर और द्विपक्षीय स्तर पर। रवांडा को भारतीय सहायता 2008 और 2011 में भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठकों में भारत द्वारा की गई घोषणाओं पर मुख्य रूप से आधारित है।

पहली भारत - अफ्रीका मंच शिखर बैठक (आई ए एफ एस-1) के बाद रवांडा को अफ्रीकी संघ द्वारा भारत - अफ्रीका व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वी टी सी) की मेजबानी के लिए नामित किया गया। मशीनरी तथा उपकरण को संचालित किया जा चुका है तथा संस्थान को दिसम्बर, 2014 में रवांडा प्राधिकारियों को सौंप दिया गया था। सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए केंद्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने जनवरी, 2015 में संस्थान का उद्घाटन किया था।

एक पैन - ई ए सी कृषि बीज उत्पादन - सह - प्रदर्शनी केंद्र को आई ए एफ एस-।। के दौरान संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। रवांडा सरकार ने संस्थान की स्थापना के लिए भूमि की पहचान कर ली है। विशेषज्ञों के एक भारतीय दल ने परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए नवम्बर, 2014 में किगाली का दौरा किया।

आई ए एफ एस-।। के दौरान किगाली में एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (एफ टी एल) (अनुमानत: 2 मिलियन अमरीकी डालर) को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। आवश्यक करार पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा अपेक्षित उपकरण प्राप्ति की जा रही है।

आई ए एफ एस-II के अंतर्गत, भारत ने एक अखिल - अफ्रीकी संस्थान अर्थात भारत - अफ्रीका उद्यशीलता विकास केंद्र (आई ए ई सी डी) की स्थापना करने का प्रस्ताव था। आवश्यक एम ओ यू को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग्रामीण रवांडा में 35 स्कूलों में सौर विद्युतीकरण को भारत से अनुदान सहायता के अंतर्गत 2014 में पूर्ण किया गया था।

आर्थिक संबंध :

न्याबारोंगो नदी पर एक 28 मेगावाट हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर परियोजना को पूर्ण किया जा चुका है तथा भारत सरकार को 80 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के अंतर्गत संचालित किया गया है। परियोजना ने रवांडा की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता को 25 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

भारत निर्यात लक्षित सिंचाई कृषि परियोजना के विकास (एवं इसके विस्तार) के लिए 120 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण की कुल सीमा को बढ़ा दिया है। परियोजना में उपजाऊ भूमि के 6500 हेक्टेयर में अधिक की सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा पानी के रोड का कार्य एवं कृषि क्रियातंत्र और कृषि उत्पाद के उत्पादन उपरांत संसाधन के लिए संसाधन इकाईयों की स्थापना शामिल है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी चल रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य :

पैन- अफ्रीका ई-परियोजना के अंतर्गत किंग फैसल अस्पताल तथा शिक्षा महाविद्यालय में वर्ष 2009 में रवांडा में क्रमश: दूर-चिकित्सा तथा दूर-शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए जिसका उद्देश्य रवांडा के चिकित्सकों को भारतीय चिकित्सकों से परामर्श करने में सक्षम बनाना था और उच्च गुणवतपूर्ण चिकित्सा परामर्श एवं रोगियों के इलाज को सुनिश्चित किया जा सके तथा रवांडा के छात्रों के लिए किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

भारत रवांडा निवासियों के लिए सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा के लिए तरजीही स्थान है। जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है, भारत में रवांडा से चिकित्सा सेवा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

	चिकित्सा वीजा	चिकित्सा परिचर वीजा
2012	290	175
2013	444	246
2014	493	263

रवांडा के विद्यार्थी भारत को गुणवत्तायुक्त और सस्ती शिक्षास्थान के रूप में भी देखते हैं। पिछले तीन वर्षों में इस मिशन द्वारा रवांडा के नागरिकों को 1582 विद्यार्थी वीजा जारी किए गए हैा ।

भारत सरकार आई टी ई सी, आई सी सी आर, सी वी रमन फेलोशिप तथा विशेष कृषि छात्रवृत्ति के तहत भारत में पूर्णत: वित्त पोषित अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों को पूरा करने के

लिए रवांडा के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के नागरिकों को हर साल छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करती है। वर्ष 2015-16 के दौरान रवांडा को इस तरह की 53 छात्रवृत्तियों की पेशकश की जा रही है।

वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (वी आई टी) में किगाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (के आई एस टी) के संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण और वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षकों की किगाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रतिनियुक्ति को सुगम बनाने के लिए वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान और किगाली विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने 2001 में एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर किया। रवांडा सरकार के शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के साथ एम ओ यू के अनुसार वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान (वी आई टी) 2002 से अपने संस्थान में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और आई टी पाठ्यक्रमों में रवांडा के छात्रों को शिक्षा भी प्रदान करता है।

खुली सरकार पर भारत अमरीकी वार्तालाप के अंतर्गत एक भारत- अमरीका -रवांडा तृपक्षीय खुली सरकार प्लेटफार्म पहल विकसित की गई जिससे भागीदार देशों को मुफ्त साफ्टवेयर डाउनलोड करने तथा एक साइट बनानेकी सुविधा मिली जिससे नागरिकों को नवीनता, आर्थिक विकास तथा पारदर्शिता हेतु सरकारी आंकड़ों तक अभिगम की सुविधा प्राप्त होगी।

रक्षा सहयोग :

सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में भारत का रवांडा से सहयोग बढ़ रहा है। रवांडा के रक्षा अधिकारियों को हर साल भारत में अधुनातन प्रशिक्षण सुविधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यापार एवं वाणिज्य :

भारत और रवांडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ी है । यद्यपि व्यापार मूल्य के संबंध में 2012 - 2013 के लिए 78.10 अमरीकी डालर के स्तर पर ही रहा है।

(मिलियन अमरीकी डालर में) स्त्रोत राष्ट्रीय रवांडा बैंक; 1 अमरीकी डालर - 690.455 रवांडा फ्रैंक)

वर्ष	**2012**	**2013**
भारत से निर्यात	159.93	220.52
रवांडा से आयात	0.99	0.24
कुल द्विपक्षीय व्यापार	160.92	220.76

यद्यपि, शेष व्यापार भारत की ओर झुका हुआ है, भारत रवांडा के निर्यात को बढ़ावा देता रहा है। रवांडा भारत के कम विकसित देशों को दिए जा रहे सीमा शुल्क मुक्त टैरिफ अधिमानता स्कीम का लाभ उठा सकता है। भारत द्वारा रवांडा को किए जाने वाले निर्यात में अन्य चीजों के साथ-साथ औषधि, मीट, साइकिल सहित वाहन, प्लास्टिक और मशीनरी आदि शामिल है।

भारतीय समुदाय

अनुमान है कि लगभग 2800 भारतीय नागरिक तथा पी आई ओ रवांडा में रहते हैं। रवांडा में रहने वाला भारतीय समुदाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ रवांडा के तहत एकजुट है। भारतीय समुदाय के प्रति रवांडा सरकार का रवैया सकारात्मक है। 1994 के नरसंहार के दौरान भारत सरकार द्वारा भारतीयों को रवांडा से बुजुमबुरा और नैरोबी भेजते समय रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट (आर पी एफ) और सरकारी सेवकों द्वारा बाध नहीं पहुंचाई गई।

रवांडा की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की सक्रिय भूमिका को रवांडा सरकार और लोगों द्वारा खूब सराहा जाता है। काबुए चीनी कारखाना, जो रवांडा में एकमात्र शुगर रिफाइनरी है, का स्वामित्व माधवानीज के पास है। यूरेम्सरा, एकमात्र आधुनिक वस्त्र मिल जो किगाली के गिसोपी में स्थित है, का संचालन भारतीय नागरिक श्री किशोर जीवनपुत्र करते हैं । सल्फो रवांडाजो साबुन और प्रसाधन फैक्ट्री है, के मालिक पी आई ओ श्री ताजदीन जफर हैं।

सांस्कृतिक संबंध :

उम्मीद है कि भारतीय एवं स्थानीय समुदाय के मनोरंजन के लिए गोवा की एक नृत्य मंडली जुलाई में रवांडा के दौरे पर जाएगी।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय उच्चायोग, कंपाला की वेबसाइट **:**
http://hci.gov.in/kampala/

*****

अगस्त, 2015